The Hon. Member has reframed to the movement and the Police etc. in Bihar I respect Shri Jai Parkash Narain very much. I would suggest that instead of demanding the dissolution of the State Assembly if they help in the Campaign against the small-pox, everybody would be benefited.

श्रीमती विभाघोष गोस्वामी (नवद्वीप) : इस बात में दो मत नहीं हैं कि यह सरकार चेचक पर नियंत्रण करने में बुरी तरह असफल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई चेतावनी के बावजूद तथा इन सभी वर्षों में चेचक उन्मूलन कार्यक्रमों के बावजूद अप्रैल, 1973 में चेचक के 87,000 से अधिक मामले जिनमें में 1500 से अधिक व्यक्तियों की मौत हुई और 1974 में 1, 15, 000 लोगों को चेचक निकली जिसमें से 17,000 से अधिक लोगों की मौतें हुई और क्या कारण है कि सरकार स्थिति का सामना नहीं कर पायी है।

लोक लेखा समिति ने अपने 124वें प्रतिवेदन में कहा है कि उसे सरकार के काम को देख कर पूर्णतया निराशा हुई है।

देश में शिक्षित, अर्धशिक्षित और अशिक्षित लोग हैं। इसके अतिरिक्त शहरी जन संख्या अर्ध शहरी जन संख्या और ग्रामीण जन संख्या है। हमें यह बताया जाना चाहिये कि किन लोगों में चेचक अधिक होती है।

वक्तव्य में कहा गया है कि लोगों में काफी अधिक अन्धविश्वास है यह अन्धविश्वास सामाजिक-आर्थिक कारणों से है। इस बारे में सरकार क्या कर रही है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि वास्तविक स्थिति को बदलने के लिये वह क्या कर रहीं है? सब से महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सरकार का चेचक के पूर्ण उन्मूलन के लिये क्या करने का विचार है?

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य और पूर्व स्पष्टीकरण के उत्तर में बताने का प्रयास किया है, चेचक का अभियान पूरी तरह सफल न होने का मुख्य कारण प्राथमिक टीका सभी लोगों द्वारा न लगाया जाना है। हम देश के प्रत्येक व्यक्ति को इसे लगाने में समर्थ नहीं हो पाये हैं। हमें विशेषकर दुर्गम क्षत्रों तथा समाज के अधिक कमजोर वर्गों की ओर ध्यान देना है।

आर्थिक तथा भाषायी पृथक आंकड़े भी प्राप्त हो जायगे। किन्तु इस में कुछ समय लगेगा। इस समय तो हमें इस भयंकर स्थिति का सामना करना है।

अन्धविश्वास को विधान द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। अन्धविश्वास केवल तभी दूर हो सकता है जब शिक्षा का प्रसार हो और लोक मत तैयार किया जाये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि समूचे देश के ससद-सदस्य तथा विधायक हमें सहायता दें तो शीघ्र ही इस अन्धविश्वास को दूर किया जा सकता है।

भूमिगत आणविक विस्फोट परीक्षण के बारे में वक्तव्य

Statement Re. Underground Nuclear Explosion Experiment

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रोनिक्स मन्त्री तथा अंतरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि परमाणु ऊर्जा आयोग ने 18 मई, 1974 को प्रातः

8 बजकर 5 मिनट पर, राजस्थान के रेगिस्तान में 100 मीटर से भी ज्यादा की गहराई पर, भूमिगत परमाणु विस्फोट करने का एक परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। यह परीक्षण, उसी अनुसंधान एवं विकास कार्य का एक अंग था जो कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये करने के हमारे देश के लक्ष्य के अनुरूप हमारे परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा किया जा रहा है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने 15 नवम्बर, 1972 को लोक सभा में कहा था कि "परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा उन परिस्थितियों का अध्ययन किया जा रहा है जिनमें शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये किये जाने वाले ऐसे भूमिगत परमाणु विस्फोट; जिनसे वायुमंडल दूषित न हो, भारत के लिये आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद सिद्ध हो सकते है।" उसके ठीक एक वर्ष बाद, 15 नवम्बर, 1973 को मैंने राज्य सभा के माननीय सदस्यों को सूचित किया था कि परमाणु ऊर्जा आयोग इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। मैंने यह भी बताया था कि विस्फोटों के परिणामस्वरूप वायुमंडल एवं जीवधारियों पर पड़ सकने वाले प्रभावों से उत्पन्न समस्याओं का संतोषजनक समाधान प्राप्त हो जाने के बाद, शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिये भूमिगत विस्फोट करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि 18 मई को किये गये सफल परीक्षण के परिणामस्वरूप कोई ऐसी रेडियो-सक्रियता उत्पन्न नहीं हुई जिससे वायुमंडल दूषित हुआ हो। रेडियो सक्रियता की मात्रा इतनी अच्छी तरह से नियन्त्रित रही कि विस्फोट के एक घंटे के भीतर ही वैज्ञानिकों का एक दल विस्फोट-स्थल के 30 मीटर ऊपर उड़ा था तथा भूमि पर भी, विस्फोट स्थल से 250 मीटर की दूरी तक पहुंचा। किन्तु इस दल ने किसी भी तरह का रेडियो-सक्रियता-जनित संदूषण नहीं पाया। परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा अब इस विस्फोट के परिणामों का अध्ययन किया जा रहा है। इस अध्ययन को पूरा करने में लगभग छः महीने का समय लगने की सम्भावना है। विज्ञान की परम्पराओं के अनुरूप ही, परमाणु ऊर्जा आयोग का यह विचार है कि इस परीक्षण के परिणामों को विज्ञान-जगत के लाभ के लिये प्रकाशित किया जाए।

इस परीक्षण में काम में लाई गई सारी सामग्री एवं सभी उपकरण भारत में ही तैयार की गई थी तथा इससे संबंधित सभी वैज्ञानिक भी भारतीय थे। भारत ने इस परीक्षण को करने में न तो किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून अथवा स्वामित्व तथा न ही किसी देश को दिए गये अपने वचन का उल्लंघन किया है।

इस परीक्षण की प्रतिक्रिया अलग-अलग देशों में अलग-अलग रही है। जबकि अधिकतर विकासशील देशों ने परमाणु ऊर्जा का उपयोग शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये करने की दिशा में इस परीक्षण का स्वागत, इसे भारत द्वारा किये गये अनुसंधान एवं विकास कार्य के एक कदम के रूप में किया है, कुछ को छोड़कर शेष विकसित देशों की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं रही है। संयुक्त राज्य अमरीका ने एक ओर तो इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण की सेफगार्ड-प्रणाली से सम्बंधित समझौतों का पालन किया है, तथा इस विस्फोट में अमरीका से प्राप्त सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है, तो दूसरी ओर उसने यह भी दोहराया है कि उसकी सरकार की नीति आणविक अस्त्रों के विस्तार के विरुद्ध है। रूस की प्रक्रिया यह रही है कि भारत ने आणविक विस्फोटों का उपयोग शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये करने की टैकनोलौजी के क्षेत्र में विश्व के अन्य देशों के स्तर पर रहने के एक अनुसंधान-कार्यक्रम को चलाया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष को इस परीक्षण की सफलता के लिए फ्रांस के परमाणु ऊर्जा आयोग से बधाई-संदेश प्राप्त हुआ है। विस्फोट की सूचना चीन ने सरकारी

पर बिना किसी टिप्पणी के दी है तथा जापान की सरकार ने विस्फोट पर अपना अफसोस जाहिर ा है।

कनाडा तथा हमारे पड़ोसी देश, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया इस बारे में तीव्र रही है। कनाडा इस ात से तो संतुष्ट है कि भारत ने दोनों देशों के मध्य विद्यमान किसी समझौते का उल्लंघन नहीं किया है, तु उसके विदेशी मामलों के राज्य मंत्री ने यह कहा है कि सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों को बन्द ने तथा परमाणु विस्फोट करने की टैक्नोलौजी का प्रसार रोकने के लिये अन्तराष्ट्रीय स्तर पर किए ये प्रयासों को इस परीक्षण से जबरदस्त धक्का पहुंचा है।

कनाडा सरकार के प्रतिनिधियों ने इस बारे में जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे भारत सरकार मत नहीं है। मैंने बारम्बार निश्चित रूप से कहा है कि हमारी नीति परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल न्तिपूर्ण कार्यों के लिए करने की है। मैंने यह बात भी खासतौर से कही है कि परमाणु अस्त्रों का ाम करने का हमारा बिल्कुल इरादा नहीं है। भारत सरकार को इस बात की पूरी आशा है कि ाडा की सरकार इस परीक्षण की पृष्ठभूमि से सहमत होगी तथा उसे समझेगी। मैंने इस वक्तव्य में पहले इस तथ्य का उल्लेख किया है कि इस टैक्नोलौजी में हुई प्रगति का पुनरीक्षण हमारे परमाणु ा आयोग द्वारा सैद्धान्तिक एवं परीक्षणात्मक दृष्टियों से किया जा रहा है। हमने अपने इस इरादे को पा कर नहीं रखा था तथा सारी दुनिया को जाहिर कर दिया था। अगर इसका मतलब समझने में ाडा की सरकार और भारत सरकार के बीच कोई मतभेद पैदा हो गये हैं तो भारत सरकार को यह ा है कि यह सभी मतभेद दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच चल रही बातचीत के द्वारा संतोषजनक प से दूर कर लिए जायेंगे।

पाकिस्तान की सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा बार-बार न्यूक्लियर ब्लैकमेल के बारे में जो कुछ हा जाता है वह भारत सरकार की समझ में नहीं आता है। मैंने इस परीक्षण के शान्तिपूर्ण स्वरूप तथा ार्थिक उद्देश्यों को प्रधान मंत्री श्री भुट्टो को लिखे अपने पत्रों में स्पष्ट कर दिया है। मैंने यह भी कहा कि अगर आपसी समझ और विश्वास का समुचित वातावरण तैयार कर लिया जाता है तो भारत ाणविक क्षेत्र में अपनी टैक्नोलौजी में पाकिस्तान कभी उसी प्रकार से साझीदार बनाना चाहता है जिस कार से अन्य देशों को। मैं इस आश्वासन को एक बार फिर से दोहराना चाहती हूं तथा आशा करती कि पाकिस्तान की सरकार इस सम्बंध में भारत सरकार की स्थिति को स्वीकार करेगी।

पाकिस्तान की सरकार ने यह भी दोष लगाया है कि रेडियो-सक्रियता उसके देश तक पहुंची । इस बारे में मैं यह बताना चाहती हूं कि ऐसा होना एक असम्भव बात थी तथा इसका कारण यह था कि न तो रेडियो-सक्रियता वायुमंडल तक पहुंच पाई थी तथा न ही रेडियो-सक्रियता से युक्त कोई बादल ठा था। इसके अलावा, जैसाकि वर्ष के इस मौसम में आम तौर पर होता है, हवा विपरीत दिशा में बह ही थी और सिद्धान्त रूप से भी किसी तरह की भी रेडियो-सक्रियता पाकिस्तान तक कभी नहीं हुंच सकती थी। यह बात विशेष रूप से जोर देकर कहना चाहती हूं कि 18 मई, 1974 को हवा क्षिण से पश्चिम की तरफ बह रही थी।

शान्तिपूर्ण परमाणु परीक्षणों के सम्भावित उपयोगों के बारे में प्रगतिशील देशों के वैज्ञानिकों द्वारा अनेक रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी हैं। अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण ने परमाणु विस्फोटों के शान्तिपूर्ण उपयोगों के बारे में 1970, 1971 तथा 1972 में पैनल मीटिंगों का आयोजन किया था तथा पैनल के एक सदस्य के रूप में भारत इन सभी मीटिंगों में उपस्थित हुआ था। शान्तिपूर्ण परमाणु

विस्फोटों से सम्बन्धित घटना क्रिया-विज्ञान एवं स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदन, 1970 की भूमिका में ऐसी परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है जिनके लिये शान्तिपूर्ण विस्फोटों को काम में लाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यहां निम्नलिखित उद्धरण देना पर्याप्त रहेगा :—

> "पूर्णत: नियन्त्रित परमाणु विस्फोट (ऐसे विस्फोट जो कि भूमि की सतह से बाहर नही होते) बहुत सी परियोजनाओं के लिये प्रयुक्त किये जा सकते हैं। औद्योगिक स्तर पर, गैस तथा तेल प्राप्त करने के लिये प्रायोगिक स्तर पर परीक्षण किये गये है तथा उन परीक्षणों के परिणाम संतोषजनक रहे हैं। इसके अलावा, जो ऐसे परीक्षणों के परिणाम स्वरूप गड्ढे बन जाते है, वे भूमिगत गैस तथा तेल का संग्रह करने, परमाणु बिजली-घरों तथा रासायनिक संयंत्रों से निकलने वाले रेडियो-सक्रियता युक्त अपशिष्ट पदार्थों को भण्डारित करने, शिला-तेलों के भण्डारों से वहीं पर तेल अलग करने, तथा विस्फोटों के परिणामस्वरूप टूटे कम ग्रेड के धातुकों की लीचिंग वहीं पर करने आदि जैसी परियोजनायें चलाने के लिये भविष्य में आर्थिक महत्व के सिद्ध हो सकते हैं। इन परियोजनाओं में से अन्तिम परियोजना एक सदस्य राष्ट्र, भारत के लिये विशेष रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है तथा वह देश इस तरीके से बहुत कम ग्रेड वाली अलोह धातुओं के भण्डारों का उपयोग कर सकता है और इस तरह से वह इन धातुओं के आयात के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बन सकता है और अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है।"

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमने यह परीक्षण हाल ही में किया है तथा हमें इसके परिणाम छः महीने बाद प्राप्त होंगे, किसी भी खास स्थान पर इस टैक्नोलौजी का कोई खास उपयोग कर सकने की बात करने का समय अभी नहीं आया है। इस प्रकार की किसी भी परियोजना को आर्थिक दृष्टि से उपयोगी तथा सम्भव बनाने के लिए, परीक्षण सम्बन्धी और आंकड़े प्राप्त करना जरूरी है।

माननीय सदस्य इस बात पर गौर करेंगे कि ऊपर मैंने जिन पैनल मीटिंगों का उल्लेख किया है उनमें अधिकांश विकसित देशों ने भाग लिया है तथा उन मीटिंगों में हुए विचार-विमर्श में इस बात पर बल दिया गया था कि शान्तिपूर्ण परमाणु विस्फोटों के क्षेत्र में किया जाने वाला कार्य निश्चित रूप से ही अनुसंधान तथा विकास-कार्यक्रमों की श्रेणी में आता हैं। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए भारत की समझ में यह बात नहीं आती है कि हमारे देश की आलोचना यह कह कर क्यों की जाती है कि शान्तिपूर्ण विस्फोटों के लिये आवश्यक टैक्नोलौजी और हथियार बनाने के कार्यक्रम के लिये आवश्यक टैक्नोलौजी में कोई अन्तर नहीं है।

कोई भी टैक्नोलौजी अपने आप में बुरी नहीं होती है ; किस भी टैक्नोलौजी की अच्छाई या बुराई इस बात पर निर्भर करती है कि उसका प्रयोग राष्ट्रों द्वारा किस प्रकार से किया जाता है। भारत किसी भी मामले में भेदभाव करने के सिद्धान्त में विश्वास नहीं करता तथा टैक्नोलौजी भी इसका अपवाद नहीं है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरी प्रार्थना है कि इस वक्तव्य पर चर्चा की जाये। सामान्य बजट पर चर्चा करते समय परमाणु ऊर्जा के विषय पर चर्चा कभी भी नहीं की जाती। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस पर चर्चा की जाये।

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। अतः श्री स्वर्ण सिंह